

RoDTEP योजना का वसितार

सरोत: द हद्रि

भारत सरकार ने नरियातकों के लयि [नरियातति उत्पादों पर शुल्कों और करों में छुट \(RoDTEP\) योजना](#) को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। यह कदम बढ़ते अमेरिकी टैरफि और वैश्वकि व्यापारकि अनश्चितताओं से जूझ रहे नरियातकों के लयि राहत लेकर आया है।

RoDTEP योजना

- **परचिय और उद्देश्य:** वर्ष 2021 में शुरू की गई यह योजना नरियातति वस्तुओं के उत्पादन और वतिरण के दौरान लगने वालेकरों, शुल्कों और शुल्कों की प्रतपूरति करती है।
 - यह उन लागतों को शामिल करती है, जनिकी प्रतपूरतिअन्य केंद्रीय, राज्य या स्थानीय कर व्यवस्थाओं के तहत नहीं की जाती है।
 - वापसी दरें 0.3% से 3.9% तक हैं, जो सभी नरियात वस्तुओं पर लागू होती हैं।
 - यह विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप है और पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लयि एक व्यापकएंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वति की जाती है।
- **लाभार्थी:** घरेलू टैरफि क्षेत्र (DTA) इकाइयाँ, अग्रमि प्राधकिरण (AA) धारक, [वशिष आर्थकि क्षेत्र \(SEZ\) इकाइयाँ](#), नरियातोनमुख इकाइयाँ (EOU)।
- **महत्त्व:** मार्च 2025 के अंत तक RoDTEP योजना के तहत कुल संवतिरण लगभग **57,000 करोड रुपए** को पार कर गया था, जो [भारत के व्यापारकि नरियात](#) को समर्थन देने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकति करता है।
- **नीतगित नहितिार्थ:**
 - वशिष रूप से वशिष आर्थकि क्षेत्रों (SEZ) और नरियातोनमुख इकाइयों (EOU) में स्थति इकाइयों के लयि नरितर नरियात वृद्धिको प्रोत्साहति करता है।
 - बजटीय सीमाओं के भीतर कार्य करता है, जसिसे राजकोषीय वविकशीलता उजागर होती है।
 - कठनि समय में नरियात क्षेत्र को समर्थन देने की सरकार की प्रतबिद्धता को सुदृढ़ करता है।

और पढ़ें: [RoDTEP योजना](#)